

# International Journal of Social Science and Education Research



ISSN Print: 2664-9845  
ISSN Online: 2664-9853  
Impact Factor: RJIF 8.00  
IJSSER 2023; 5(2): 89-92  
[www.socialsciencejournals.net](http://www.socialsciencejournals.net)  
Received: 05-07-2023  
Accepted: 11-08-2023

## सरिता

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,  
अदिति महाविद्यालय, दिल्ली  
विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

## सामाजिक विज्ञान का विवेचनात्मक अध्ययन

सरिता

DOI: <https://doi.org/10.33545/26649845.2023.v5.i2b.68>

### सारांश

यह शोध लेख स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले सामाजिक अध्ययन विषय के संबंध में है। इस शोध लेख में सामाजिक अध्ययन की विषयवस्तु के चयन, शिक्षण, मूल्यांकन इत्यादि का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया है। इस शोध में सामाजिक अध्ययन कैसा विषय है, इसमें किन-किन अनुशासनों का समावेश होता है, इसकी वर्तमान में सार्थकता क्या है, इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विद्वानों जिनका समग्र शिक्षा जगत से संबंध रहा है उनके दृष्टिकोणों का विवेचनात्मक अध्ययन करने के साथ-साथ, NEP 2020 में क्या संभावनाएँ हैं इसका भी अध्ययन किया गया है। इस शोध लेख में निष्कर्ष रूप में पाया गया कि सामाजिक अध्ययन अन्य कई अनुशासनों से विषयवस्तु ग्रहण करता है तथा इसकी इतिहास की विषयवस्तु पर विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं। इस विषय की उपादेयता समसामयिक संसार में आज भी बनी हुई है। देश में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, देशभक्ति, स्वावलंबन जैसे गुणों को विद्यार्थियों और भविष्य में नागरिकों में विकसित करने में इस विषय का महत्त्व सर्वाधिक है।

**कूटशब्द :** सामाजिक विज्ञान, विचारधारा, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण, विषयवस्तु

### प्रस्तावना

#### सामाजिक विज्ञान – एक स्कूली विषय के रूप में

सामाजिक विज्ञान एक स्कूली विषय है जिसमें कई विषयों का समावेश है। द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (1994) के अनुसार सामाजिक विज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के सामाजिक व सांस्कृतिक पक्षों से है जिसमें सांस्कृतिक मानवविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक मानवविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक भूगोल तथा शिक्षा के वे क्षेत्र जिनका संबंध अधिगम के सामाजिक संदर्भों एवं सामाजिक ढाँचे के साथ विद्यालय का संबंध है, आते हैं। इतिहास भी सामाजिक विज्ञान का अंग है।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण से संबंधित एक कांग्रेस (1954) में सामाजिक विज्ञान को एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र मानते हुए अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, समाजनृत्व विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान का सम्मिलित रूप माना गया। इसमें सामाजिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को उभारा गया है। इसमें लिखा है कि यह समाज को समझने में सहायता करने, मानव की मूलभूत जरूरतों को समझने, आर्थिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक रूपों को समझने में सहायता करता है। इसमें सामाजिक विज्ञान को मानव को अपने समाज को समझने और उसकी वर्तमान व भविष्य की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान खोजने में सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञान को व्यापक अध्ययन क्षेत्र माना गया है जिसमें मानवीय संबंधों से जुड़े विभिन्न अनुशासनों का एकीकृत रूप से अध्ययन किया जाता है। NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान समाज के विविध सरोकारों को अपने अंदर समेटता है और इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, आदि विषयों की विस्तृत सामग्रियाँ सम्मिलित होती हैं। एक अर्थपूर्ण सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या अपनी पाठ्य सामग्री के चयन व गठन द्वारा विद्यार्थियों में समाज की आलोचनात्मक जानकारी विकसित करने में समर्थ होती है।

#### सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु

माइकल एप्पल (1990) ने अमेरिका के संदर्भ में पाठ्यक्रम के निर्धारण में वर्गों के इतिहास, जाति, लिंग, धार्मिक दृढ़ की भूमिका की विस्तार से चर्चा की है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसे राजनीतिक होती है और शिक्षा में लागू सभी सिद्धांत, नीतियाँ और उनका व्यवहारिक रूप तकनीकी नहीं होते, अपितु वे जातीय तथा राजनीतिक रूप पर आधारित होते हैं। इन्होंने विचार रखा है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से समाज में विद्यमान सामाजिक यथार्थ का पुनर्उत्पादन किया जाता है।

### Corresponding Author:

#### सरिता

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,  
अदिति महाविद्यालय, दिल्ली  
विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

समाज में प्रभुत्वशाली ताकतवर वर्ग अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। मार्टिन कारनाथ (1997) ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि कैसे शिक्षा का इस्तेमाल साम्राज्यवादी देश सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करने के लिए अपनी संस्कृति का साम्राज्य बढ़ाने के लिए करते थे। प्रो. कृष्ण कुमार (1992) ने पाठ्यक्रम के निर्धारण की समस्या के मूल में ज्ञान की अवधारणा और ज्ञान राशि के चयन की कसौटी की प्रमुख बातें देखी हैं – बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, शिक्षा पाने में अवसरों के वितरण की क्या स्थिति है जैसी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया है। प्रो. कृष्ण कुमार (1992) ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में दिया जाने वाला ज्ञान औपनिवेशिक ढाँचे पर आधारित होता है। स्कूली ज्ञान का चयन, शिक्षण पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम सभी के संदर्भ में औपनिवेशिक राज के साथ इनका संबंध देखा जा सकता है। अंग्रेजों ने अपने ढंग से भारतीयों की सोचने समझने की शक्ति विकसित करने का कार्य शिक्षा को माध्यम बनाकर किया।

### इतिहास

शिक्षा को शक्तिशाली वर्ग अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करता है। प्रो. कृष्ण कुमार ने अपनी पुस्तक (2001) में दर्शाया है कि एक ऐतिहासिक संघर्ष को किस तरह से भारत और पाकिस्तान में अलग-अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। किस तरह से दो देशों की विचारधारा का अन्तर एक ऐतिहासिक संघर्ष की प्रस्तुति उसकी व्याख्या में भी स्पष्ट रूप से दिखता है और विचारधारा पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। नीलादरी भट्टाचार्या (2002) ने अपने लेख में इतिहास पाठ्यपुस्तक लेखन और राजनीति के बीच संबंध देखा है। इन्होंने उन विचारों को उभारा है जिनका एन.सी.ई.आर.टी. की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के लेखन के समय ध्यान रखा गया। इन्होंने सामाजिक अध्ययन 2005 के NCF पर आधारित पाठ्यपुस्तकों के गुण बताए हैं जैसे किसी एक राष्ट्रीय अतीत का न होना, स्थानीय इतिहास से बड़े नगरों और क्षेत्रों के इतिहास की ओर जाना, दैनिक जीवन के इतिहास पर फोकस इत्यादि। उमा चक्रवर्ती (2006) ने अपनी पुस्तक में भारत में इतिहास की किस तरह की पुस्तकें उपलब्ध थीं और लिखी जाती थी इस पर चर्चा की है। इन्होंने इतिहास की पुस्तकों में तिथि और घटनाओं की भरमार, राजनीति, प्रशासन पर आधारित पुस्तकों पर जोर देखा जबकि इनमें जाति, वर्ग, लिंग आधारित आन्तरिक विरोधाभास को नहीं स्थान दिया गया था। इतिहास लेखन पर भी इन्होंने प्रश्न उठाया है। साधारण लोगों का इतिहास बहुत सी प्रमुख इतिहास की पुस्तकों में नहीं था।

वी. गीता (2009) ने भी यह दर्शाया है कि पाठ्यपुस्तकें हमेशा शहरी मध्यवर्गीय पुरुष के लिए ही लिखी गई हैं। स्त्रियों को आमतौर पर परम्परागत स्त्री की भूमिका में ही दिखाया गया है। प्रो. कृष्ण कुमार (1996) ने भी स्पष्ट किया है कि इतिहास का शिक्षण पुराने राष्ट्र राज्यों (जैसे यूरोपीय) और औपनिवेशिक बाद के राष्ट्र राज्यों में अलग तरह का है। पुराने राष्ट्र राज्यों में बच्चे विशिष्ट शीर्षक (Specific Topic) का अध्ययन करते हैं, शीर्षक प्राथमिकता की नीति है और अतीत को विभाजित करने के लिए पूर्व और पश्चात् क्रांतिकारी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में इतिहास की स्कूल की पाठ्यचर्चा और पाठ्यपुस्तकें सतत अतीत प्राचीन से आधुनिक तक के विचार के इर्दगिर्द ही संरचित है। शीर्षक प्राथमिकता की नीति नहीं है। भारत में तर्क की अपेक्षा, रटने पर फोकस रहता है। इन्होंने इस संबंध में कुछ सुझाव भी दिए हैं जैसे प्राथमिक स्रोतों का चित्रात्मक प्रदर्शन, स्थानीय संदर्भ का होना, घटनाओं के चयन की आवश्यकता बताने की अपेक्षा खोजने के मौके देना, व्यक्तित्वों पर फोकस की अपेक्षा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण पर फोकस करना।

निवेदिता मेनन (2010) ने अपने लेखन में NDA शासनकाल के कुछ वर्षों के पहले और बाद की लिखी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की पड़ताल करने का प्रयास किया है। इन्होंने इतिहास के दो अर्थों (Senses) में भेद करने पर जोर दिया है। पहला अर्थ एक आधुनिक अनुशासन के रूप में, दूसरा एक राजनैतिक हस्तक्षेप के रूप में। पहले अर्थ में इतिहास 'वस्तुनिष्ठ सत्य' नहीं है इसको वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इतिहास वह है जो इतिहासकार लिखता है। दूसरे रूप में इतिहास एक राजनैतिक हस्तक्षेप है। इन्होंने पाया कि NCF 2005 को शिक्षकों के लिए असहज मुद्दों जैसे द्वंद्व तथा असमानता पर शिक्षकों के पक्षपातों के प्रति मौन है। इनका मानना है कि छद्म 2005 का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान शिक्षण का क्या अर्थ है इसके बारे में रेडिकल (Radical) पुनर्विचार करना है।

### राजनीति विज्ञान

मनीष जैन (2005) ने अपने लेख में 'सामाजिक अध्ययन' शब्द के उद्भव को भारत तथा विश्व के संदर्भ में देखा है। इन्होंने नागरिक शास्त्र का सामाजिक अध्ययन का अंग बनने की प्रक्रिया तथा एक स्कूली विषय के रूप में इसके महत्त्व को उभारा है। साथ ही पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक पश्चात् काल में नागरिक शास्त्र के उद्देश्य एवं उपयोग को भी उभारा है। एलक्स एम. जार्ज (2007) ने नागरिक शास्त्र की परम्परागत पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन किया है कि कैसे बच्चे राजनीति एवं सरकार की समझ बनाते हैं। इन्होंने विभिन्न संस्थाओं जैसे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा इत्यादि के विषय में बच्चों के नजरिये का अध्ययन किया है। यह पुस्तक हमें नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों की प्रकृति और अवधारणाओं के बारे में बच्चों की समझ जानने में सहायता करती है। रश्मि पालीवाल ने भी अपने लेख (1995) में सरकार क्या है? कैसे बनती है? कैसे काम करती है? आदि मुद्दों पर बच्चों की समझ जानने की कोशिश की है। अमन मदन (1995) ने अपने लेख 'नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में नागरिकों की छवि' में लिखा है कि NCERT की नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो इनके लिए 'राज्य' (शासन) का अध्ययन नागरिक शास्त्र का पूर्ण पर्याय है। यह सच है कि 'राज्य' की गतिविधियाँ लोगों के जीवन में बहुत से पक्षों को छूने लगी हैं, पर भारत की युवा पीढ़ी के लिए छोटे-बड़े व्यापारियों, किसानों, कारीगरों के बारे में सीखना भी कम जरूरी नहीं है। इन्होंने लिखा है कि नागरिक शास्त्र के द्वारा यह भी उभारना चाहिए कि हमें हर बात के लिए राज्य या अन्य किसी बाहरी संस्था का मुँह ताकते रहने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी समस्याओं का हल खुद भी निकाल सकते हैं। जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे विचारों का केवल सिद्धांतवादी प्रस्तुतीकरण किया गया है। बहुत से भारतीय शहर और कस्बे भी अनियोजित ढंग से बने हुए हैं किन्तु सम्पूर्ण पुस्तक में केवल गाँवों को ही 'अनियोजित' होने की उपाधि दी गई है। गाँवों की एक अति सरलीकृत छवि ही सामने रखी गई है – गाँव यानी छप्पर वाले मकान। इन पुस्तकों में शहरी औद्योगिक समाज की मान्यताओं और प्रतीकों को ग्राम्य जीवन की मान्यताओं से बेहतर व प्रगतिशील बताया गया है।

### भूगोल

भूगोल की पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में यमुना सनी (2010) ने अपने लेख में मध्यप्रदेश SCERT व एकलव्य की पाठ्यपुस्तकों की पड़ताल की है और खासतौर पर यह तलाश करने की कोशिश की है कि भूगोल की पाठ्यपुस्तकें मनुष्य तथा प्रकृति के सर्वव्यापक संबंध को किस तरह सामने लाती हैं। SCERT की पाठ्यपुस्तकों में लेखक ने मनुष्य तथा प्रकृति के द्वंद्व की स्थिति, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित लोगों को अपराधबोध झेलना देखा है वहीं एकलव्य की पाठ्यपुस्तकों को

पर्यावरण भूगोल को निर्धारित करता है दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें वर्णित क्षेत्र सामाजिक ढाँचे को निर्मित करने वाले कारकों में न तो उत्पादन प्रक्रिया को और न ही संघर्ष के भूगोलों को शामिल करते हैं।

रश्मि पालीवाल (1997) अपने लेख 'पर्यावरण क्या, क्या नहीं' में पर्यावरण शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयामों पर नजर डाली है और इस बात पर जोर दिया है कि स्थानीय पर्यावरण के साथ-साथ दूसरे पर्यावरण की समझ भी बच्चों में विकसित करना जरूरी है तथा समझ विकसित करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है।

यमुना सनी व रश्मि पालीवाल ने अपने लेख 'पृथ्वी पर गर्मी और सर्दी' में पृथ्वी पर ऋतुएँ कैसे बदलती है इस पर बड़ी कक्षा के बच्चों की समझ का अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि छात्रों के दिमाग में भी पृथ्वी की गति और मौसम परिवर्तन की छवि साफ नहीं है। इस प्रकार इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं भूगोल सामाजिक विज्ञान के मूल विषय हैं।

### सामाजिक विज्ञान का शिक्षण

सामाजिक विज्ञान में कई विषयों का समावेश होता है और इसकी प्रकृति अंत-अनुशासनात्मक है। इसका शिक्षण भी महत्वपूर्ण बन जाता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संबंध में 'एकलव्य' के कार्यक्रम से भी हमारी समझ में बढ़ोतरी होती है।

एकलव्य का 'सामाजिक अध्ययन शिक्षण एक प्रयोग' (1994) से इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की पुरानी पुस्तकों की खामियों की समझ बनती है तथा एकलव्य ने इन विषयों की नई पाठ्यपुस्तकें बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा, कैसे विषयवस्तु का चुनाव किया इसकी जानकारी मिलती है।

प्रो. पूनम बत्रा (2010) ने अपनी पुस्तक में एकलव्य की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम और शिक्षण का विश्लेषण किया है और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा है। इन्होंने पाया कि एकलव्य के पाठ्यक्रम में ज्ञान का सृजन बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा निजी खोज और विमर्शी चिंतन के द्वारा किया जाता है। सीखने वाले की छवि सकारात्मक, सक्रिय, सोचने वाले के रूप में है। एकलव्य की पाठ्यपुस्तकों में कहानी का शिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल हुआ है। कहानी के पात्र सचेत, सक्रिय और जिज्ञासु हैं। पाठ्यपुस्तकें सीखने वाले के पर्यावरण से जुड़ी हैं। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को वस्तुओं, विचारों, घटनाओं और परिस्थितियों की तुलना करने को बढ़ावा देती हैं। एकलव्य की पाठ्यपुस्तकें बच्चों में अवलोकन, तुलना, समस्या समाधान, तर्क इत्यादि कौशलों का विकास करती हैं। इन्होंने पाया कि इनमें बच्चों के लिए लिखने के पर्याप्त अवसरों की कमी है जिनको दूर किया जाना चाहिए। इसमें चित्रकला, क्ले पर भी फोकस कम है। इसके बावजूद एकलव्य की पाठ्यपुस्तकें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संबंध में नई दृष्टि देती है।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर बने राष्ट्रीय फोकस समूह ने सामाजिक विज्ञान संबंधी प्रचलित धारणाओं की चर्चा की तथा नए पाठ्यक्रम के लिए कुछ आधारभूत बिन्दु सुझाएँ - विषय वस्तु (सूचनाओं) के भार को कम करके प्रासंगिक सूचनाओं में से ही चुनना तथा अवधारणाओं तथा सामाजिक-राजनैतिक यथार्थों के विश्लेषण के योग्यता के विकास पर जोर, पठन-पाठन में स्थानीय विषय वस्तु को शामिल करना, मूल्य संबंधी सरोकारों को बढ़ावा देना जैसे पर्यावरण, जाति/वर्ग, असमानता जैसी समस्याओं पर अंतर्विषयक विधि से चर्चा करके पाठ्यपुस्तकों को बच्चों की विचार प्रक्रिया और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना, विषयों के बीच अंतर्संबंध पर जोर दिया है। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों पर चर्चा में स्त्री-परिप्रेक्ष्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय फोकस समूह ने शिक्षण प्रशिक्षण की कमी की बात भी कही है। इन्होंने सेवा पूर्व

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के पुनरीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है।

एलक्स एम. जार्ज एवं अमन मदन की पुस्तक एक मैनुअल है जिसमें नई एप्रोच को तर्कपूर्ण ढंग से स्पष्ट किया है और कैसे नई पाठ्यपुस्तकें प्रभावी रूप से इस्तेमाल की जा सकती है, दर्शाया है।

### मूल्यांकन

रश्मि पालीवाल (2010) ने अपने लेख में स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के बदलाव एवं मूल्यांकन के अनुभवों की चर्चा की है। इन्होंने स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा की है जयश्री ने अपने लेख (2010) में यह दिखाया है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। इन्होंने सामाजिक विज्ञान विशेषकर इतिहास के मूल्यांकन को अर्थपूर्ण बनाने के तरीके सुझाएँ हैं। सरिपर्णा (2010) ने अपने लेख में विद्यार्थियों के मूल्यांकन में प्रोजेक्ट, फिल्ड वर्क एवं खोज की आवश्यकता पर फोकस किया है। इस तरह से सामाजिक विज्ञान में बेहतर मूल्यांकन कैसे किया जाए इस संबंध में ये लेख हमारी समझ को बेहतर बनाते हैं।

विद्वानों ने सामाजिक अध्ययन के महत्त्व को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है एवं उससे जुड़ी चिंताएँ भी प्रस्तुत की हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक अध्ययन ऐसा स्कूली विषय है जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान में और अधिक बढ़ गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान भारत को दिशा देने के लिए उसे सशक्त बनाने में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी गई है।

### राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति चार भागों में है : जिसमें भाग 1. स्कूली शिक्षा, 2. उच्चतर शिक्षा, 3. अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे एवं 4. क्रियान्वयन की रणनीति है। इसका लक्ष्य सभी के लिए समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चिता के साथ-साथ शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम और शिक्षण के संदर्भ में कहा गया है कि यह समग्र, एकीकृत, आनंददायी एवं रुचिकर हो तथा शिक्षा समावेशी एवं समतामूलक हो। इस शिक्षा नीति में शिक्षक पर भी बहुत महत्त्व दिया गया है। इसमें अध्यापक शिक्षा में शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ-साथ अद्यतन प्रगति एवं साथ ही भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान परम्पराओं, जनजातीय परंपराओं, लोकाचार के प्रति शिक्षकों की जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अन्य सुझावों के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दिए इसके सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं।

### निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान जिसके लिए स्कूली स्तर पर सामाजिक अध्ययन शब्दावली का उपयोग किया जाता है एक अंतःअनुशासनात्मक विषय है। इसमें इतिहास, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान आधारभूत विषय है एवं अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय भी इसमें सम्मिलित हैं। इन विषयों की विषयवस्तु के चयन के आधार भी समय एवं राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित होते पाए गए हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता एवं महत्त्व वर्तमान समय में पहले से अधिक बढ़ गया है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर अत्यधिक बल दिया गया है। सुचारु शिक्षण के सहारे ही इस विषय के उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावना प्रबल बन जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा की समग्रता से चर्चा की गई है एवं समावेशी एवं समतामूलक समाज में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। अध्यापक शिक्षा में भी क्रांतिकारी परिवर्तन कर समर्पित शिक्षा व्यवस्था को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ता प्रदान

करने का प्रयास है इससे सामाजिक विज्ञान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में और आगे बढ़ सकेगा ऐसी संभावना है।

### संदर्भ

1. Apple W. Michael. Education and Power, Routledge and Kegan Paul, Boston, London, Melbourne and Hoesly; c1982.
2. Apple W. Michael. Ideology and Curriculum, Routledge, New York and London; c1990.
3. Batra, Poonam. (Ed.) Social Science Learning in Schools: Perspective and Challenges, Sage, New Delhi; c2010.
4. Bhattacharya, Neeladri. Teaching History in Schools: The Politics of Textbooks in India, History Workshop Journal. 2002;67:99-110.
5. Chakravarti, Uma. Everyday Lives, Everyday Histories: Beyond the Kings and Brahmins of Ancient India, Tulika Books: New Delhi, Chapter on: History as Practice; c2006. p. 16-30.
6. Geeta V, Selvam S, Bhog D. Textbook Regimes: A Feminist Critique of Nation and Identity, Tamilnadu, Nirantar, Delhi; c2009.
7. Alex GM. Children's Perception of Sarkar, A Critique of Civics Textbooks, Eklavya; c2007.
8. Alex GM, Amman M. Teaching Social Sciences in Schools, NCERT's New Textbook Initiative, Sage; c2009.
9. Jain, Manish. Social Studies and Civics, Past and Present in the Curriculum, Economic and Political, Weekly; c2005. p. 1939-1942.
10. Kumar, Krishna. Learning from Conflict, Orient Longman, New Delhi; c1996. p. 25-41.
11. Kumar, Krishna. Political Agenda of Education (A Study of Colonialist and Nationalist Ideas), Sage Publication, New Delhi / Newbury Park/London; c1991.
12. Kumar, Krishna. Prejudice and Pride, School Histories of Freedom. Struggle in India and Pakistan, Penguin, Viking; c2001.
13. Kumar, Krishna. What is Worth Teaching, Orient Longman, New Delhi; c1992.
14. Menon Nivedita. (Chapter), History, Truth and Nation Contemporary Debates on Education in India, Understanding Contemporary India Critical Perspective, Edited by Achin Vanaik & Rajeev Bhargava, Orient Black Swan; c2010. p. 179-199.
15. Nambiar, Jayashree. Beyond Retention, Meaningful Assessment in Social Sciences, Learning Curve, Azim Premji, Foundation: Bangalore. 2010;15:106-110.
16. National Curriculum Framework 2005, Position Paper, National Focus Group on Teaching of Social Sciences, National Council of Educational Research and Training; c2006.
17. Paliwal R. Assessment of Social Science in Schools Our Experiences, Experiments and Learning Curve, Issue XV, Azim Premji, Foundation, Bangalore; c2010. p. 95-105.
18. Round Table Conference on the Teaching of Social Science in South Asia, Hind Union Press, New Delhi; c1954. p. 11.
19. Sriparna. Role of Projects, Fieldwork and Discovery in Assessment, Learning Curve, Azim Premji Foundation, Bangalore. 2010;15:118-120.
20. The New Encyclopaedia Britannica. President Publishing Group. 1994;27:316.
21. कारनाथ मार्टिन अनुवादक—कृष्णकांत मिश्र. सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और शिक्षा, नई दिल्ली, ग्रंथ शिल्पी, 1997
22. पालीवाल, रश्मि. जो गौरिशंकर की समझ में न आए – संदर्भ 7, पृष्ठ 47–52, सितम्बर–अक्टूबर, 1995
23. पालीवाल, रश्मि. 'पर्यावरण क्या क्या नहीं', पृष्ठ 47–56, संदर्भ 19. सितम्बर–अक्टूबर, 1997
24. मदन, अमन, नागरिक शास्त्रा की पुस्तकों में नागरिकों की छवि, पृष्ठ 88–95, संदर्भ 7, सितम्बर–अक्टूबर, 1995
25. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2020
26. India, Ministry of Education <https://www.education.gov.in>...PDF>
27. सामाजिक अध्ययन शिक्षण एक प्रयोग, एकलव्य, जनवरी, 1994
28. सन्नी, यमुना. स्वीकृत ज्ञान भूगोल में निहित राजनैतिक संकेतार्थ, पृष्ठ 59–76, अंक 14. संदर्भ सितम्बर–अक्टूबर, 2010.
29. सन्नी, यमुना व पालीवाल, रश्मि. आया समझ में? संदर्भ–7, पृष्ठ 43–47, सितम्बर–अक्टूबर, 1995